हिमाचल का ट्रांस-गिरी क्षेत्र और हट्टी समुदाय

सन्दर्भ

केंद्र द्वारा हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के ट्रांस गिरी क्षेत्र को आदिवासी का दर्जा देने पर विचार किया जा रहा है।

प्रमुख बिंदु

• हट्टी समुदाय 1967 से इस दर्जे की मांग कर रहा था, जब 1967 में उत्तराखंड (तत्कालीन यूपी) के पड़ोसी जौनसार बावर क्षेत्र में समुदायों को दर्जा दिया गया था।
• दोनों क्षेत्रों के समुदायों में समान रीति-रिवाज, भाषा और ड्रेस कोड हैं क्योंकि दोनों एक ही सिमरौली साम्राज्य के अधीन थे।
• हिमाचल प्रदेश सरकार ने क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था।
• यदि प्रस्ताव को वास्तव में लागू किया जाता है, तो क्षेत्र में रहने वाली सभी प्रभावशाली जातियों, अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्रदान किया जाएगा।

जनजातीय स्थिति

• अनुसूचित क्षेत्र को अनुच्छेद 244(1) के तहत पांचवीं अनुसूची के तहत नामित किया गया है जबकि आदिवासी क्षेत्र को संविधान की छठी अनुसूची के अनुसार अनुच्छेद 244 (2) के तहत नामित किया गया है।
• अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने के लिए सरकार द्वारा अपनाए जाने वाले मानदंड हैं:
जनजातीय आबादी की प्रधानता।
क्षेत्र की सघनता और उचित आकार।
एक व्यवहार्य प्रशासनिक इकाई जैसे जिला, ब्लॉक या तालुक।
पड़ोसी क्षेत्रों की तुलना में क्षेत्र का आर्थिक पिछड़ापन।

हट्टी समुदाय के बारे में

• समुदाय, जिसमें तीन लाख से अधिक लोग हैं, का नाम उनके आस-पास के शहरों में 'हाट' नामक छोटे बाजारों में अपने घर में उगाई जाने वाली फसलों को बेचने की उनकी सदियों पुरानी पेशेवर प्रथा के नाम पर रखा गया है।
• वे यमुना की दोनों सहायक नदियों, गिरि और टोंस नदियों के बेसिन में हिमाचल प्रदेश-उत्तराखंड सीमा के आसपास रहते हैं। टोंस दोनों राज्यों के बीच की सीमा का प्रतीक है। आज तक, इस समुदाय के सदस्यों को मुख्यधारा में नहीं लाया गया है और अधिकांश पशु पालन और कृषि पर निर्भर हैं।
• पंचायत प्रणाली की स्थापना के बावजूद वे अभी भी खुंबली - पारंपरिक परिषद का पालन करते हैं।

शहरी सहकारी बैंकों के लिए चार स्तरीय नियामक ढांचा

संदर्भ

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने मौजूदा शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए अलग-अलग नियामक नुस्खों के साथ एक साधारण चार स्तरीय नियामक ढांचा अपनाने का फैसला किया है।

प्रमुख बिंदु

• आरबीआई का निर्णय यूसीबी पर एनएस विश्वनाथन समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर आधारित है।
• समिति ने बैंकों की जमाराशियों के आकार और उनके संचालन के क्षेत्र के आधार पर एक चार-स्तरीय नियामक ढांचे की सिफारिश की थी।

प्रमुख स्वीकृत सिफारिशें

• एक जिले में कार्यरत टियर 1 शहरी सहकारी बैंकों के लिए न्यूनतम निवल मूल्य ₹2 करोड़ और अन्य सभी शहरी सहकारी बैंकों (सभी स्तरों के) के लिए ₹5 करोड़।
• जो शहरी सहकारी बैंक आवश्यकता को पूरा नहीं करते हैं, उन्हें संशोधित मानदंडों के लिए सुगम संक्रमण की सुविधा के लिए मध्यवर्ती मील के पत्थर के साथ पांच साल का एक उडान पथ प्रदान किया जाएगा।
• बेसल I पर आधारित मौजूदा पूंजी पर्याप्तता ढांचे के तहत टियर 1 बैंकों के लिए न्यूनतम सीआरएआर आवश्यकता 9% है।
• टियर 2, टियर 3 और टियर 4 शहरी सहकारी बैंकों के लिए, उनकी पूंजी संरचना को मजबूत करने के लिए न्यूनतम सीआरएआर को 12% तक संशोधित किया जाएगा।
• शहरी सहकारी बैंकों के लिए शाखा विस्तार के लिए स्वचालित मार्ग शुरू करना जो संशोधित वित्तीय रूप से सुदृढ़ और अच्छी तरह से प्रबंधित (FSWM) मानदंडों को पूरा करते हैं।
• उन्हें पिछले वित्तीय वर्ष के अंत में शाखाओं की संख्या के 10% तक नई शाखाएँ खोलने की अनुमति दें।

ईआईए नियम संशोधित

संदर्भ

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) नियमों में संशोधन को अधिसूचित किया है, जिसमें कुछ श्रेणियों की परियोजनाओं को पूर्व पर्यावरण मंजूरी से छूट दी गई है।

नई छूट प्राप्त परियोजनाएं

• सामरिक और रक्षा महत्व की राजमार्ग परियोजनाएं, जो नियंत्रण रेखा से 100 किमी दूर अन्य स्थानों में हैं।
• कोयला, लिग्नाइट या पेट्रोलियम उत्पादों जैसे 15% तक के सहायक ईंधन का उपयोग करने वाले बायोमास या गैर-खतरनाक नगरपालिका ठोस अपशिष्ट पर आधारित 15 मेगावाट तक के थर्मल पावर प्लांट
• टोल प्लाजा जिन्हें बड़ी संख्या में वाहनों की जरूरतों को पूरा करने के लिए टोल संग्रह बूथों की स्थापना के लिए अधिक चौड़ाई की आवश्यकता होती है।
• हवाईअड्डे के मौजूदा क्षेत्र में वृद्धि किए बिना टर्मिनल भवन के विस्तार से संबंधित मौजूदा हवाई अड्डों में विस्तार गतिविधियां।
• बंदरगाहों की सीमा बढ़ाना जो विशेष रूप से मत्स्य सम्पदा को संभालने का काम करता है और छोटे मछुआरों का ध्यान रखता है।

क्यों छोड़ रहे भारतीय अपनी नागरिकता

सन्दर्भ

गृह मंत्रालय ने कहा कि 1.6 लाख से अधिक भारतीयों ने 2021 में अपनी भारतीय नागरिकता छोड़ दी।

प्रमुख बिंदु

• 2021 में, 163,370 भारतीयों ने अपने भारतीय पासपोर्ट छोड़े। 2019 और 2020 में यह संख्या क्रमश: 144,017 और 85,256 थी।
• इन भारतीयों द्वारा अपने देश की नागरिकता को त्यागने का कारण, जिसका अर्थ यह भी है कि उन्हें अपने भारतीय पासपोर्ट सरेंडर करने पड़ते हैं, "व्यक्तिगत" थे।

नागरिकता पर कानून:

• भारतीय संविधान और नागरिकता कानून दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं देते हैं।
• पिछले साल फरवरी में और मंगलवार को संसद के साथ साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, कुल मिलाकर, 932,276 भारतीयों ने 2015 और 2021 के बीच अन्य देशों के पक्ष में अपनी नागरिकता का त्याग किया।
• नवंबर 2021 में गृह मंत्रालय द्वारा साझा किए गए डेटा में कहा गया है कि 2016 और 2020 के बीच 10,645 विदेशी नागरिकों ने भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन किया, जिनमें से अधिकतम (7,782) पाकिस्तान से और 795 अफगानिस्तान से आए। इनमें से 4,177 व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता प्रदान की गई।
• 13,383,718 (13 मिलियन) भारतीय नागरिक वर्तमान में विदेशों में रह रहे हैं।
• 2016 और 2020 के बीच कुल 452 "स्टेटलेस" व्यक्तियों ने भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन किया था, लेकिन यह नहीं पता था कि कितने लोगों को नागरिकता दी गई और उन्होंने किस क्षेत्र से नागरिकता के लिए आवेदन किया।
• स्टेटलेस व्यक्तियों को उन लोगों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जिनकी पहचान किसी देश, यहां तक कि उनके गृह देश द्वारा नहीं की जाती है।

ग्रामीण बिजली आपूर्ति

संदर्भ

आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2013 की पहली तिमाही के पहले दो महीनों के दौरान हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक के गांवों को आपूर्ति की गई बिजली राष्ट्रीय औसत से काफी नीचे रही है।

प्रमुख बिंदु

• अखिल भारतीय आधार पर, वित्त वर्ष 2012 के अप्रैल-मई में गांवों को आपूर्ति की गई बिजली की अवधि 21.48 घंटे है, जबकि पूरे वित्त वर्ष 2012 में यह 20.61 घंटे थी।

FY22 में बिजली की आपूर्ति

• शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों में, महाराष्ट्र ने वित्त वर्ष 2012 के दौरान 23.16 घंटे के लिए अपने गांवों को बिजली प्रदान की। इसी तरह, गुजरात ने 23.50 घंटे पश्चिम बंगाल (23.38 घंटे), आंध्र प्रदेश (23.62 घंटे) और मध्य प्रदेश (19.35 घंटे) के लिए बिजली प्रदान की।
• सबसे कम प्रदर्शन करने वाले राज्यों में, हरियाणा ने वित्तीय वर्ष 22 में 16.26 घंटे बिजली प्रदान की।

हिमाचल प्रदेश ने 13.26 घंटे , कर्नाटक (17.56 घंटे), त्रिपुरा (19.93 घंटे) और बिहार (20.39 घंटे) बिजली प्रदान की।
• गर्मी की चरम मांग: 29 अप्रैल को, दिन के दौरान भारत की सबसे अधिक बिजली की मांग 207 गीगावाट (GW) दर्ज की गई, जो वार्षिक आधार पर 13 प्रतिशत अधिक है, और पूरी की गई ऊर्जा 4578 मिलियन यूनिट (MU) थी। .
• सरकार ने 24x7 बिजली आपूर्ति हासिल करने के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू की हैं।
दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (DDUGJY)।
एकीकृत विद्युत वितरण योजना (आईपीडीएस)।
पुर्नोत्थान वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस)।

अन्य महत्त्वपूर्ण खबरें

भारत और मालदीव के बीच न्यायिक सहयोग

सन्दर्भ
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और मालदीव के बीच न्यायिक सहयोग के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी।

प्रमुख बिंदु
• केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और मालदीव के न्यायिक सेवा आयोग के बीच न्यायिक सहयोग के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दे दी है।
• न्यायिक सहयोग के क्षेत्र में भारत और अन्य देशों के बीच यह आठवां समझौता ज्ञापन है। यह समझौता ज्ञापन अदालत के डिजिटलीकरण के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के लाभों का दोहन करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा और दोनों देशों में आईटी कंपनियों और स्टार्ट-अप के लिए एक संभावित विकास क्षेत्र हो सकता है।
• कानून और न्याय के क्षेत्र में सहयोग पर इस समझौते पर हस्ताक्षर से दोनों देशों के बीच अच्छे संबंधों को और गति मिलेगी।

भारत-नामीबिया ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

सन्दर्भ
भारत सरकार और नामीबिया गणराज्य की सरकार ने भारत में चीता को ऐतिहासिक श्रेणी में स्थापित करने के लिए वन्यजीव संरक्षण और टिकाऊ जैव विविधता उपयोग पर एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) में प्रवेश किया है।

समझौता ज्ञापन के मुख्य प्रमुख क्षेत्र हैं:
• चीतों के पूर्व के क्षेत्रों में जहां से वे विलुप्त हो गए थे, उनके संरक्षण और बहाली पर विशेष ध्यान देने के साथ जैव विविधता संरक्षण।
• दो देशों में चीता संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विशेषज्ञता और क्षमताओं का आदान-प्रदान,
• अच्छी प्रथाओं को साझा करके वन्यजीव संरक्षण और टिकाऊ जैव विविधता उपयोग:

तकनीकी अनुप्रयोग,
• वन्यजीव आवासों में रहने वाले स्थानीय समुदायों के लिए आजीविका सृजन के तंत्र, और जैव विविधता का सतत प्रबंधन।
• जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण शासन, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन, प्रदूषण और अपशिष्ट प्रबंधन और पारस्परिक हित के अन्य क्षेत्रों के क्षेत्रों में सहयोग।
• वन्यजीव प्रबंधन में प्रशिक्षण और शिक्षा के लिए कर्मियों का आदान-प्रदान।
• चीता की आईयूसीएन स्थिति: संवेदनशील।

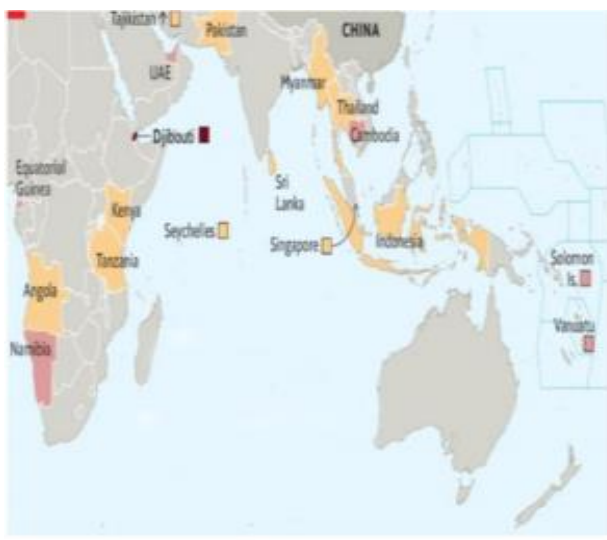

यूरोप में रिकॉर्ड तोड़ हीटवेव

सन्दर्भ

यूरोप में तापमान स्पेन से ब्रिटिश द्वीपों तक बढ़ रहा है और पूर्व में फैल रहा है।

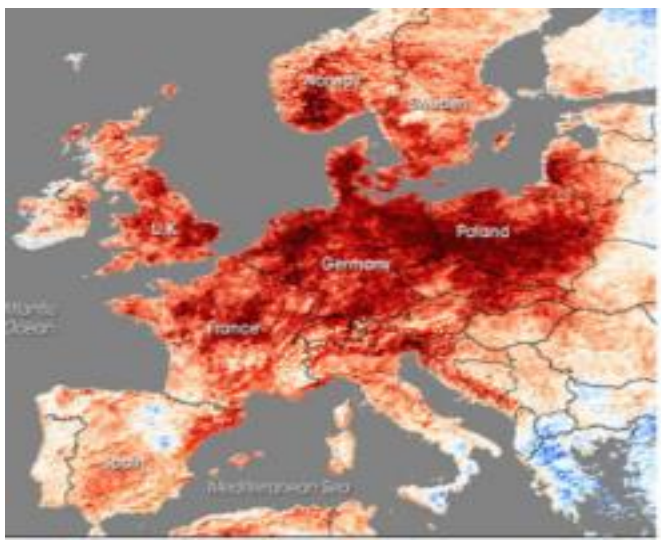

प्रमुख बिंदु

• कई देशों में गर्मी की वजह से जंगलों में आग लग रही है, और अधिकांश महाद्वीप लंबे समय तक सूखे की चपेट में है।
• 19 जुलाई 2022 को, ब्रिटेन ने लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे पर पहली बार 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाते हुए अपना अब तक का उच्चतम तापमान दर्ज किया।
• ग्लोबल वार्मिंग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है क्योंकि तापमान 19वीं सदी के अंत की तुलना में औसतन लगभग 1.1 डिग्री सेल्सियस अधिक है।
• अन्य कारक भी हैं, जिनमें से कुछ में वायुमंडल और महासागर का संचलन शामिल है, जो यूरोप को एक गर्मी की लहर गर्म स्थान बनाता है।
• आर्कटिक में वार्मिंग, जो दुनिया के अन्य हिस्सों की तुलना में बहुत तेजी से हो रही है, भी एक भूमिका निभा रही है।
• जैसे-जैसे आर्कटिक तेज गति से गर्म होता है, उसके और भूमध्य रेखा के बीच तापमान का अंतर कम होता जाता है।
• इससे ग्रीष्म ऋतु की हवाओं में कमी आती है, जिसका प्रभाव मौसम प्रणालियों के लंबे समय तक चलने में होता है।

शाकाहारी उत्पाद

सन्दर्भ

एपीडा ने शाकाहारी उत्पाद के निर्माण के लिए मानकों का मसौदा तैयार करने के लिए पैनल का गठन किया।

प्रमुख बिंदु

• इस कदम से विदेशों में उभरते संयंत्र-आधारित वैकल्पिक बाजारों को टैप करने में मदद मिलेगी।
• मांग में तेजी: कोविड के बाद, विदेशी बाजारों में पौधों पर आधारित मांस के विकल्प की मांग में तेजी आई है क्योंकि उपभोक्ता स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो गए हैं।
• संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप, जापान, कोरिया और ऑस्ट्रेलिया सहित अन्य देशों में शाकाहारी और पौधे आधारित मांस प्रोटीन उत्पादों की अंतरराष्ट्रीय बाजार में बड़ी मांग है।
• भारत में शाकाहारी या पौधे आधारित प्रोटीन उत्पादों की काफी संभावनाएं हैं क्योंकि हमारे पास देश में कच्चे माल की अच्छी उपलब्धता है, जो शाकाहारी उत्पादों के लिए एंजाइम, एडिटिव्स और रंगों के रूप में उपयोग किए जाते हैं।
• शाकाहारी उत्पाद: शाकाहारी भोजन में अंडे, मांस, डेयरी उत्पाद और अन्य सभी पशु-व्युत्पन्न सामग्री का सेवन शामिल नहीं है।

विशेष ऋण वसूली न्यायाधिकरण

सन्दर्भ

बैंकों ने उच्च मूल्य के मामलों (₹100 करोड़ और उससे अधिक) में त्वरित निर्णय और वसूली के लिए विशेष ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी) और ऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरण (डीआरएटी) स्थापित करने के लिए वित्त मंत्रालय से याचिका दायर की है।

प्रमुख बिंदु

• देश भर में मौजूदा न्यायाधिकरणों - 39 डीआरटी और पांच डीआरएटी - में 1.5 लाख से अधिक लंबित मामलों की पृष्ठभूमि में यह अनुरोध आया है।
• यह उच्च पेंडेंसी तब भी है जब केंद्र सरकार ने 2018 में डीआरटी पर ऋण वसूली आवेदनों के लिए वित्तीय सीमा को दोगुना करके ₹20 लाख कर दिया था।
• ट्रिब्यूनल और अपीलीय ट्रिब्यूनल बैंकों और वित्तीय संस्थानों के कारण ऋण की वसूली अधिनियम, 1993 के तहत स्थापित किए गए हैं।
• प्रावधानों के अनुसार, आवेदन को यथासंभव शीघ्रता से निपटाया जाना चाहिए , प्राप्त होने के 180 दिनों के भीतर आवेदन का निपटान करें और दो सुनवाई में कार्यवाही को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए।

• ट्रिब्यूनल के पास सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत दीवानी न्यायालय की शक्ति है, लेकिन वे इससे बाध्य नहीं हैं। अधिनियम के अनुसार, उन्हें प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित किया जाएगा और उन्हें अपनी प्रक्रियाओं को विनियमित करने की शक्ति प्राप्त होगी।

बौधायन सुल्बसूत्र

सन्दर्भ

कर्नाटक सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर एक स्थिति पत्र ने पाइथागोरस प्रमेय पर चर्चा को पुनर्जीवित किया है।

प्रमुख बिंदु

• बौधायन सुल्बसूत्र, वैदिक भारतीयों द्वारा किए जाने वाले अग्नि अनुष्ठानों (यज्ञों) से संबंधित सबसे पुराना सूत्र है।
• अपने पहले अध्याय में, यह प्रमेय द्वारा व्यक्त गणितीय संबंध को संदर्भित करता है, इसके पहले अध्याय में एक विशिष्ट श्लोक में संदर्भित करता है।
• यह कहता है - विकर्ण की लंबाई के साथ खींची गई एक रेखा ऐसा क्षेत्र बनाती है जो ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज पक्ष एक साथ बनाते हैं।
• विभिन्न आकृतियों में वेदियों (वेदी) के निर्माण के दौरान समीकरण चलन में आया - समद्विबाहु त्रिभुज, आयत, सममित समलंब।
• बिना किसी प्रत्यक्ष प्रमाण के, सूत्रों को भाषाई और अन्य माध्यमिक ऐतिहासिक विचारों के आधार पर लगभग 800 ईसा पूर्व का माना जाता है।

बौधायन के अन्य गणितीय कार्य

• एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई उसकी भुजाओं के पदों में परिकलित करना, जो 2 के वर्गमूल के सूत्र के बराबर है।
• एक वर्ग के क्षेत्रफल के लगभग बराबर और इसके विपरीत एक वृत्त की रचना करना।

अरगलया

सन्दर्भ

इस शब्द का प्रयोग सार्वजनिक आंदोलन के पर्याय के रूप में किया जा रहा है जिसके कारण श्रीलंकाई सरकार का पतन हुआ।

प्रमुख बिंदु

• सिंहली शब्द का अर्थ है संघर्ष।
• लोगों की दैनिक सभाओं का वर्णन करने के लिए इसका व्यापक रूप से उपयोग किया जा रहा है।

व्हाट्सएप बैंकिंग सेवाएं

सन्दर्भ

भारत के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के ऋणदाता, भारतीय स्टेट बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए बैंकिंग को आसान बनाने के लिए अपनी व्हाट्सएप बैंकिंग सेवाएं शुरू की हैं।

प्रमुख बिंदु

• एसबीआई ग्राहक व्हाट्सएप का उपयोग करके कुछ बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं, जो कई लोगों के काम आ सकती हैं क्योंकि उन्हें अब ऐप डाउनलोड करने या एटीएम जाने की आवश्यकता नहीं है। एसबीआई के ग्राहक अपने खाते की शेष राशि प्राप्त कर सकते हैं और व्हाट्सएप पर मिनी स्टेटमेंट देख सकते हैं।
• भारतीय स्टेट बैंक अपने क्रेडिट कार्ड धारकों को एसबीआई कार्ड व्हाट्सएप कनेक्ट के नाम से प्लेटफॉर्म के माध्यम से व्हाट्सएप-आधारित सेवाएं भी प्रदान करेगा।
• इसके माध्यम से, एसबीआई क्रेडिट कार्ड ग्राहक अपने खाते का सारांश, रिवॉर्ड पॉइंट, बकाया राशि की जांच कर सकते हैं और कार्ड से भुगतान कर सकते हैं।

MCQ, Current Affairs, Daily Pre Pare